इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 01 अगस्त 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

भारतय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
केन्द्रीय बैंकिंग----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------5
अर्थव्यवस्था ----------5
विदेशी मुद्रा----------6
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 6
शब्दावली ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति - जुलाई 2010

मौद्रिक उपाय :

1. बैंक दर 6.0 % की दर पर कायम रखी गई।
2. पुनर्खरीद (Repo) दर 5.5 % से 25 आधार अंक (bps) बढ़ा कर 5.75 % कर दी गई।
3. प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर 4 % से 50 आधार अंक बढ़ा कर 4.5 % कर दी गई।
4. अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 6 % पर कायम रखा गया।

वित्तीय बाज़ार से सम्बन्धित उपाय :

वर्षानुवर्ष आधार पर मुद्रा आपूर्ति (M3) की वृद्धि मार्च 2010 के अंत में 16.8 % से घट कर 2 जुलाई 2010 को 15.3 % के स्तर पर आ गई, जिससे बैंक जमाराशियों में मंदी का पता चलता है। सावधि जमाराशियों में मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पारस्परिक निधियों (MFs) द्वारा किए गए जमाराशियों के आहरण के कारण कमी आ गई। घटती जमा वृद्धि की पृष्ठभूमि में उच्चतर ऋण वृद्धि का वित्तीयन करने के लिए बैंकों ने पारस्परिक निधियों में उनके निवेशों को अपहृत करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पुनर्खरीद पटल तक पहुंचने का मार्ग अपनाया।

विनियामक उपाय :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) सहित मौद्रिक नीति की वर्तमान परिचालन कार्यविधि की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल का प्रस्ताव किया गया है।

2. अधिक आवृत्ति वाली नीतिगत समीक्षा : अब भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक तिमाही समीक्षा के बाद मोटे तौर पर लगभग डेढ़ महीने के अंतराल पर तिमाही के मध्य में समीक्षा आरंभ करेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिमाही के मध्य में की जाने वाली ये समीक्षाएं जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च महीनों में होंगी।

उद्देश्य :

1. मांग से सम्बन्धित दबावों तथा स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करते हुए साधारण मुद्रास्फीति।
2. स्थिर वृद्धि में सहायक वित्तीय स्थितियां बनाए रखना।
3. नीतिगत कार्रवाइयों के अधिक प्रभावी प्रेषण से सुसंगत चलनिधि की स्थितियां सृजित करना।
4. अल्पावधिक दरों की अस्थिरता को घटा कर अपेक्षाकृत कम कॉरीडर में लाना।

मुख्य घटनाएं

भारतीय रुपये को सुस्पष्ट प्रतीक मिला

भारतीय रुपये को एक ऐसा सुस्पष्ट, अभिज्ञेय प्रतीक प्राप्त हो गया है, जो एक करोड़ खरब से अधिक वाली अर्थव्यवस्था की शक्ति को निरूपित करता है। भारतीय मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं - अमरीकी डालर, ब्रिटिश पौण्ड, जापानी येन और यूरो - जिनके पास स्वयं अपने प्रतीक मौजूद हैं, की विशिष्ट मंडली में शामिल हो गई है।

र

उक्त प्रतीक में द्योतक और द्योतित, दोनों ही का समावेश है। रुपये के नये प्रतीक में ऊपरी सतह पर दो ऊर्ध्वाधर लकीरों के साथ बांई तरफ दंडिका रहित देवनागरी अक्षर र ध्वनि का द्योतक है। यह महत्वाकांक्षा का द्योतन करता है। महत्वाकांक्षा है ऐसी अर्थव्यवस्थाओं, जिनके पास स्वयं अपने मुद्रा प्रतीक हैं, के साथ मिल कर भारत को एक वैश्विक शक्ति-केन्द्र के रूप में प्रक्षेपित करना। संकटग्रस्त विश्व में दूसरी सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पश्चापसारिता (resilience) इस महत्वाकांक्षा को विश्वास और प्रभावशालिता, दोनों ही प्रदान करती है।

भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग काउंटर पर प्रस्तुत की

अपने 'हरियाली अपनाएं' आन्दोलन के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चेन्नै शाखा में 'ग्रीन चैनल काउंटर' की शुरूआत की है, जिसमें ग्राहक कागज़-रहित जमा, आहरण और प्रेषण करते हैं, इस प्रकार जमा-पर्चियों, चेकों आदि की आवश्यकता समाप्त हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री ओ.पी. भट्ट का कहना है कि "खेल में परिवर्तन" की सुविधा से ग्राहकों (विशेषत: वरिष्ठ नागरिकों) का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें प्राय: तीन प्रतियों में फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्पूर्ण लेनदेन कार्ड-आधारित होता है, इस प्रकार इससे काउंटर के पीछे बैठे व्यक्ति को भी मदद मिलती है।

केवल 1 रुपये में एसबीआई खाता खोलें

भारतीय स्टेट बैंक की एक नयी, अब तक की सर्वप्रथम पहलकदमी शहरी क्षेत्रों में संघर्षरत गरीब कामगारों और लघु व्यवसायियों को केवल 1 रुपये में बैंक खाता खोलने में समर्थ बनाती है। इस नयी सुविधा को परिचालित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने जीवसांख्यिकीय (biometric) स्मार्टकार्डों की शुरूआत की है, जिसके माध्यम से वे छोटी रकमें जमा और आहरित कर सकते हैं, ब्याज अर्जित कर सकते हैं तथा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में, हैदराबाद के भिन्न -भिन्न इलाकों में शहरी गरीबों को लक्ष्यांकित करते हुए ग्राहक सेवा केन्द्र (CSPs) कहे जाने वाले 20 कियॉस्क खोले गए हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसके कारबार संपर्की (BC Partner) जियोसंसार के सहयोग से ग्राहक सेवा केन्द्रों की राष्ट्रीय शुरूआत का एक हिस्सा है। ये कियॉस्क एक कारबार संपर्की के साथ एक छोटी बैंक शाखा की भांति कार्य करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतन राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष होंगे

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्तों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समनुरूप लाने के लिए उन्हें संशोधित कर दिया है। इस मुहिम से राजकोष को पिछले बकाये के रूप में 791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लागत भार वहन करना पड़ेगा।

नये बैंकों को अपना प्रसार-क्षेत्र ग्रामीण भारत तक बढ़ाना होगा

लाइसेंस की मांग करने वाले नये बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ गंठजोड़ व्यवस्था करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे कि उन्हें अपेक्षाकृत एक व्यापक धरातल पर परिचालन आरंभ करने तथा एक ऐसे राष्ट्र में वित्तीय समावेशन के कार्य में तेजी लाने में सहायता प्राप्त हो, जिसमें आधे कृषक परिवारों को ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नये बैंक लाइसेंसों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने तथा इस आशय की अनिवार्यता लागू किए जाने की संभावना है कि नये बैंक बैंक रहित क्षेत्रों में न्यूनतम एक निश्चित संख्या में शाखाएं खोलें।

बैंकों ने धोखधड़ियों, प्रतिभूति से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने हेतु सहायता संघ गठित किए

वाणिज्यिक बैंकों के एक सहायता संघ ने लॉस डाटा कन्सॉर्सियम (कॉर्डेक्स), नामक एक नयी कम्पनी का गठन करने के लिए हाथ मिला लिया है, जो धोखधड़ियों और प्रतिभूति जोखिमों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करेगी। उक्त कम्पनी सदस्य बैंकों से बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाले परिचालन जोखिमों से सम्बन्धित मुद्दों पर परंपरागत (ऐतिहासिक) आंकड़े एकत्रित करेगी और उसका विश्लेषण करेगी। नयी कम्पनी में (भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि सहित) कुल 13 बैंक इक्विटी स्वाधिकृत करेंगे, जिसमे प्रारंभ में प्रत्येक बैंक 1 करोड़ रुपये का अंशदान करेगा। भारतीय बैंक संघ की पहल पर डाटा एकत्रित एवं विश्लेषित किए जाने के लिए नयी कम्पनी का गठन विदेशी बाज़ारों में अपनाई जाने वाली परंपरा के अनुरूप है।

केन्द्रीय बैंकिंग नीतियां एवं बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत समीक्षा की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की नियमित समीक्षा को इस समय प्रचलित तिमाही आधार की अपेक्षा अधिक आवृत्ति वाला रूप देना चाहता है। ऐसा लगता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों एवं अन्य नीतिगत लिखतों की समीक्षा करने हेतु माह में एक बार से लेकर छ: सप्ताह के घालमेल वाले पश्चिमी मॉडल का अनुकरण कर रहा है। स्पष्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस विषय पर अपने विचारों से सरकार को अवगत करा दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार के कामकाज़ के समय को परिवर्तित किया

सभी वर्णक्रम के बाज़ार सहभागियों द्वारा यह राय व्यक्त किए जाने के बाद कि सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बाज़ार के कामकाज़ का समय अनुचित रूप से लम्बा है, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों में पुनर्खरीद (Repo) में सीधे लेनदेन तथा संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋणदायी बाध्यता (CBLO) बाज़ारो, जिनमें निपटान टी + 1 आधार पर होता है, में कामकाज़ का समय सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के पूंजी अनुपात को बढ़ाए जाने की संभावना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से बैंकों के लिए अधिक पूंजी आवश्यकताएं निर्धारित किए जाने की संभावना है। "वित्तीय संकट ने पूंजी पर्याप्तता के प्रति दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया है। कम की बजाय थोड़ी अतिरिक्त पूंजी रखना बेहतर है", इस बात पर बल देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यपालक निदेशक श्री आनंद सिन्हा बताते हैं कि विश्वव्यापी वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में बासेल II मानदंडों में संशोधन पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) की एक समिति कार्य कर रही है। बढ़ी हुई अपेक्षाओं को बाद में लागू किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक जोखिम-भारित आस्तियों का 9 % न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए जाने वाले 8 % की तुलना में अधिक है। भारत में अधिकांश बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12 % से अधिक है। यूरोप ने 4 से 5 % की स्थायी पूंजी वाला मॉडल अपना रखा है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 8 % है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा विस्तारित की, सांविधिक चलनिधि अनुपात सुविधा वापस ली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए दूसरी दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) दो सप्ताह के लिए बढ़ा कर 30 जुलाई तक कर दी है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस सुविधा को नहीं विस्तारित

किया है, जिसके तहत बैंक उनकी सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) बॉण्डों की धारिता के 0.5 % तक उधार ले सकते थे। इस सुविधा का उपयोग करते हुए कोई बैंक उसका सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षित 25 % के बजाय 24.5% बनाए रख सकता था। चलनिधि समायोजन सुविधा के विस्तार से बैंकों को उनके संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन में यथेष्ट रूप से सहायता प्राप्त हो सकती थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा 26 मई को बैंकों को उनकी दैनिक चलनिधि स्थितियों को समायोजित करने तथा अग्रिम कर एवं दूरसंचार लाइसेंसों का भुगतान करने हेतु भारी मात्रा में आहरणों के बाद किसी प्रकार के असंतुलन से बचने में सहायता करने के लिए लागू की थी। अपनी दूसरी चलनधि समायोजन सुविधा की नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में (पहली नीलामी में 28,520 करोड़ रुपये के बाद) 12,455 करोड़ रुपये पूंजी लगाई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फ़र्जी योजनाओं के बारे में चेतावनी जारी की

भारतीय जनता को प्राप्त हो रहे काफी बड़ी संख्या में फ़र्जी लॉटरी प्रस्तावों तथा विदेशों से सस्ती निधियों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेणी I वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अतिरिक्त रूप से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। लॉटरी योजनाओं में सहभागिता के उद्देश्य से किसी भी रूप में विप्रेषण विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत निषिद्ध है। इसके अलावा ये प्रतिबंध मुद्रा प्रसार योजना जैसे विभिन्न नामों के तहत विद्यमान लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभागिता के लिए अथवा इनाम / पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के लिए विप्रेषणों पर भी लागू होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्फ्रा रुपया ऋणों के पुनर्वित्तीयन के लिए ईसीबी के माध्यम से अंतरण वित्तपोषण को मंजूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधारभूत सुविधा कम्पनियों को इस प्रकार के विदेशी मुद्रा ऋणों के माध्यम से अंतरण वित्तपोषण प्राप्त करने की अनुमति दे कर उनके द्वारा लिए जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) को अभिशासित करने वाले मानदंडों को और भी शिथिल कर दिया है। इसके पूर्व यह छूट बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़क एवं बिजली क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनियों पर ही लागू होती थी। अधारभूत सुविधा परियोजना का विकास करने वाली कम्पनी के लिए उक्त ऋण के अंतरण वित्तपोषण हेतु घरेलू बैंकों तथा विदेशी उधारदाताओं के साथ एक ऐसा त्रिपक्षीय करार करना आवश्यक होगा, जिसकी न्यूनतम अवधि आवश्यक रूप से सात वर्ष की होनी चाहिए। इस लेनदेन में संलग्न घरेलू बैंक अंतरण वित्तपोषण से सम्बन्धित मानदंडों द्वारा अभिशासित होंगे तथा उन्हें इस प्रकार के वित्तपोषण की गारंटी देने की अनुमति नहीं होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

वर्ष 2009-10 में आधारभूत वित्तीयन बढ़ कर 41 % हुआ

सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा आधारभूत सुविधा क्षेत्र को दिए गए कुल उधारों की रकम में 40.8 % की वृद्धि हुई और वह मार्च 2009 में 2,69,972 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2009-10 में 3,80,122 करोड़ रुपये हो गई। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उधारों में 38 % की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे वे 2,44,304 करोड़ रुपये से बढ़ कर 3,37.018 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कम्पनी (IIFC), जो आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों से अधिक की अवधि हेतु ऋण उपलब्ध कराती है, ने मार्च, 2010 तक विविध मुख्य परियोजनाओं के लिए 24,376 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत रकम के समक्ष 11,837.27 करोड़ रुपये की रकम संवितरित की। हालांकि, इसकी एक रोचक प्रवृत्ति यह रही कि मुख्य क्षेत्रों के प्रति छोटे एवं मध्यम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर उनके कुछेक अपेक्षाकृत बड़े प्रतिपक्षियों की तुलना में अधिक रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष आधार दर की कठिनाई उपस्थित

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनकी आधार दर उनके निजी क्षेत्र के प्रतिपक्षियों की तुलना में अधिक है, को कठिनाई का अनुभव होना आरंभ हो गया है। बिल भुनाई से सम्बन्धित गतिविधि, जिसमें कोई बैंक बिल को उसके देय होने के पूर्व खरीद लेता है तथा बिल के मूल्य को भुनाई (बट्टा) प्रभार लगाने के बाद ग्राहक के खाते में जमा कर देता है, निजी बैंकों की ओर खिसक रही है, क्योंकि भुनाई (बट्टा) दर अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आधार दर से कम है। बैंक विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट कुछेक श्रेणियों को छोड़कर, आधार दर से कम दर पर उधार नहीं दे सकते।

पहली तिमाही में बैंक ऋणों और जमाराशियों में बढ़ोत्तरी

ऐसा लगता है कि बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष 2011 की पहली तिमाही उत्साहवर्धक रही है। 2 जुलाई 2010 को समाप्त पखवाड़े में ऋणों एवं जमाराशियों में क्रमश: 91,973 करोड़ रुपये और 1,15,162 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की स्थिति के विवरण के अनुसार इसके पहले वाले पखवाड़े में जहां बैंक ऋणों में 22,343 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज हुई थी, वहीं जमाराशियों में 23,761 करोड़ रुपये की गिरावट आई थी।

बैंक जमा वृद्धि में मंदी

यूरो क्षेत्र में हुई घटनाओं, जिनसे शेयर बाज़ार निरंतर आधार पर प्रभावित हो रहे हैं, के अलावा, बैंकों की जमा वृद्धि की दर में गिरावट तथा उधारों में बढ़ोत्तरी के कारण चलनिधि की स्थिति से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। समग्र जमा वृद्धि दर दिसम्बर, 2008 की 20.4 % से घट कर दिसम्बर, 2009 में 18 % रह गई। इसी अवधि के दौरान सकल बैंक ऋणों की वृद्धि दर 15.9 % से उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर 18.3 % हो गई। आईडीबीआई बैंक के कार्यपालक निदेशक (खुदरा बैंकिंग) श्री आर.के. बंसल का कहना है कि "बैंकों

को निकट भविष्य में ही अपनी जमा दरों को बढ़ाने पर विचार करना होगा। मुद्रास्फीति के अधिक होने के फलस्वरूप जमाकर्ता लम्बे समय तक जमाराशियों पर नकारात्मक प्रतिफल नहीं स्वीकार करेगा। भविष्य में इससे ऋण वृद्धि प्रभावित होगी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्खरीद (Repo) और प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (Reverse Repo) दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप चलनिधि की स्थिति अपेक्षाकृत कठिन होना अवश्यंभावी है।"

अब बैंक संदेहास्पद गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकते हैं

अब बैंक सूचित कपटपूर्ण एवं संदेहास्पद गतिविधियों के एक राष्ट्रव्यापी डाटाबेस - सिबिल डिटेक्ट की सहायता से अधिक जोखिमपूर्ण गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना तक पहुंच प्राप्त और उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। देश के प्रथम ऋण आसूचना ब्यूरो के प्रबन्ध निदेशक श्री अरुण ठुकराल आश्वस्त करते हैं कि यह डाटाबेस बैंकों के लिए नये ग्राहकों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने से पहले उचित सावधानी बरतने वाले उपकरण के रूप में काम करेगा।

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलयन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अपने साथ विलयन की दिशा में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की उक्त लेनदेन को स्वीकृति प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप एक कदम और आगे बढ़ गया है। पिछले दो वर्षों में (स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के बाद) भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलयित होने वाला यह दूसरा सहयोगी बैंक होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री सुश्री अंबिका सोनी द्वारा की गई अभिपुष्टि के अनुसार इस मुहिम से आधार, जनशक्ति और अन्य संसाधनों की दृष्टि से बड़े पैमाने की किफ़ायतें लाई जा सकेंगी।

चलनिधि की मांग के फलस्वरूप बैंकों का एसएलआर पोर्टफोलियो 34% घटा

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थूल-आर्थिक एवं मौद्रिक घटनाएं : पहली तिमाही की समीक्षा 2010-11 में बताया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) का अतिरिक्त पोर्टफोलियो एक वर्ष पहले के 2,85,491 करोड़ रुपये से 34.20% घट कर 2 जुलाई 2010 को 1,87,705 करोड़ रुपये रह गया, क्योंकि बैंकों ने विशेष सुविधाओं के माध्यम से उससे चलनिधि सहायता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, चलनिधि समायोजन सुविधा की पूनर्खरीद (Repo) विधि को ध्यान में रखते हुए बकाया आधार पर चलनिधि समायोजन सुविधा संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए समायोजित तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुरक्षण निवल मांग एवं सावधि देयताओं का 29.6 % था, जो निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात की तुलना में 4.6 प्रतिशत का आधिक्य दर्शाता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा दरों का मार्ग संकीर्ण किए जाने से अस्थिरता में कमी आएगी

पुनर्खरीद (Repo) दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि (5.5 % से 5.75) तथा प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि (4 से 4.5 %) किए जाने की भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई से ब्याज दरों में अस्थिरता को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार चलनिधि की स्थिति में अधिशेष और घाटे के बीच वाले उतार-चढ़ाव आने की संभावना है। चलनिधि समायोजन सुविधा दरों वाले मार्ग को संकीर्ण बनाने के पीछे निहित औचित्य को स्पष्ट करते हुए एचडीएफसी बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री आदित्य पुरी कहते हैं कि "अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान होने पर एक व्यापक मार्ग की आवश्यकता होती है। किन्तु अब चूंकि अर्थव्यवस्था स्थिर हो चुकी है, ऋण वृद्धि में तेजी आई है तथा ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, उक्त मार्ग को संकीर्ण किया जा सकता है।"

बैंक ऋणों में 38,913 करोड़ रुपये की कमी

दूरसंचार कम्पनियों से भारी मांग पर बढ़ने के बाद बैंक ऋणों में 17 जुलाई को समाप्त पखवाड़े के दौरान 38,913 करोड़ रुपये की कमी आ गई। इसी अवधि के दौरान बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों में 40,867 करोड़ रुपये की कमी आई। वर्षानुवर्ष आधार पर जमाराशियां 14.55 % बढ़ कर 45,91,836 करोड़ रुपये हो गईं, मांग जमाराशियों अथवा चालू खातों एवं जमा खातों (CASA) में 37,735 करोड़ रुपये की कमी आई, जबकि सावधि जमाराशियों में कमी 3,32 करोड़ रुपये की रही।

निरुद्ध ऋण

--को समाप्त पखवाड़ा	ऋण प्रवाह	वर्षानुवर्ष वृद्धि	संग्रहीत जमाराशियां	वर्षानुवर्ष वृद्धि
09 अप्रैल 10	826	17.00	43,501	16.00
23 अप्रैल 10	-26483	17.13	-23,327.90	14.97
0 7 मई 10	13,030	17.25	24,471	14.72
21 मई 10	2,406	18.04	-4,997	14.16
04 जून 10	57,895	19.12	-9,024	14.33
18 जून 10	22,343	19.59	-23,761	13.92
02 जुलाई 10	91,972.53	21.70	1,15,162	14.92
17 जुलाई 10	-38913	21.27	-40867	14.55
आंकड़े करोड़ रुपयों में		पखवाड़े के अंत में वर्षानुवर्ष वृद्धि (%)		

ऋणजाल

मार्च 2010 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 261.4 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 18.9 %) था, जिसमें मार्च 2009 में समाप्त वर्ष की तुलना में 36.9 बिलियन अमरीकी डालर अथवा 16.5 %

की वृद्धि दर्ज हुई। इस तीव्र वृद्धि का कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से सहायता में हुई वृद्धि और वाणिज्यिक उधार के साथ-साथ अनिवासी भारतीय जमाराशियों में आया उछाल था। अल्पावधिक व्यापार ऋण में भी वृद्धि दर्ज हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2008 में भारत ने विश्व के पांचवें सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश के रूप में अपना स्थान निरंतर बनाए रखा। कुल विदेशी ऋणों में बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) का अंश 27 % रहा, जिसके बाद अल्पावधिक ऋण (20 %) और अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों (18.4%) का स्थान रहा। उधारों में वृद्धि के परिणामस्वरूप देश के ऋण शोधन अनुपात में वर्ष 2008-09 के दौरान दर्ज 4.6%की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई। अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं तथा भारतीय रुपये के समक्ष अमरीकी डालर में हुए मूल्यह्रास के कारण मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर विदेशी ऋण के स्टॉक में मार्च 2009 में समाप्त वर्ष के स्तर के मुकाबले 30.4 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई।

मार्च के अंत में

मिलियन डालरों में

घटक द्वारा विदेशी ऋण	2008	2009	2010 (अनंतिम)
बहुपक्षीय	39,490	39,538	42,733
द्विपक्षीय	19,708	20,613	22,596
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	1,120	1,018	6,041
व्यापार ऋण	10,328	14,490	16,878
बाह्य वाणिज्यिक उधार	62,334	62,413	70,986
अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	43,672	41,554	48,092
रुपया ऋण	2,017	1,527	1,657
दीर्घावधिक ऋण (अ) * 1	1,78,669	1,81,153	2,08,983
अल्पावधिक ऋण * 2	45,738	43,362	52,471
कुल (1+2)*	**2,24,407**	**2,24,515**	**2,61,454**

इकॉनॉमिक टाइम्स

निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आधार दरें घोषित कीं

निजी क्षेत्र के उधारदाता आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी आधार दर 7.5% नियत करना पसंद किया है, जबकि एचडीएफसी बैंक ने उसकी न्यूनतम उधार दर 7.25% की आकर्षक दर पर रखने का निर्णय लिया है। कोटक महिन्द्रा बैंक, येस बैंक, ड्यूश बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एचएसबीसी सहित कई एक निजी और विदेशी उधारदाताओं ने अपनी आधार दरें घोषित कर दी हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनी आधार दरें नियत करने में कमोबेश सरकार द्वारा संचालित बैंकों की बराबरी की गई है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

ने अपनी आधार दरें 8% के स्तर के आसपास नियत की है, वहीं निजी क्षेत्र के उधारदाता इस क्षेत्र में अधिक आक्रामक रहे हैं।

विविध बैंकों की आधार दरें निम्नानुसार हैं :

सं.	निजी क्षेत्र के बैंक	दरें (%)
1	आईसीआईसीआई बैंक	7.50
2	एचडीएफसी बैंक	7.25
3	ऐक्सिस बैंक	7.50
4	करूर वैश्या बैंक	8.50
5	धनलक्ष्मी बैंक	7.00
6	बैंक ऑफ राजस्थान	8.00
7	फेडरल बैंक	7.75
8	इंडसइंड बैंक	7.00
9	येस बैंक	7.00
10	कोटक महिन्द्रा	7.25
11	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	7.75

सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	दरें (%)
1	भारतीय स्टेट बैंक	7.50
2	पंजाब नैशनल बैंक	8.00
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.00
4	बैंक ऑफ इंडिया	8.00
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.00
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8.00
7	देना बैंक	8.25
8	आईडीबीआई बैंक	8.00
9	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	7.75
10	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	8.25
11	केनरा बैंक	8.00
12	कारपोरेशन बैंक	7.75
13	इंडियन बैंक	8.00
14	यूको बैंक	8.00
15	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	7.75
16	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7.75

17	इलाहाबाद बैंक	7.75
18	विजया बैंक	8.25

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक एसजीएल चूककर्ताओं पर जुरमाना लगाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक सहायक सामान्य खाता-बही (SGL) खाता धारकों पर अपर्याप्त निधियों एवं प्रतिभूतियों के कारण उनके सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों का निपटान करने में असफल होने पर जुरमाना लगाएगा। इस प्रकार की चूकों को 'एसजीएल की अस्वीकृति' माना जाएगा। श्रेणीकृत जुरमाना ढांचे के तहत चूककर्ता सदस्य को प्रत्येक घटना पर जुरमाने के रूप में 5 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा। यह प्रणाली किसी एक वित्तीय वर्ष में पहली नौ घटनाओं के लिए प्रभावी होगी। दसवीं चूक पर कम्पनी को शेष वर्ष के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री के लिए एसजीएल खाते का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में मंदड़िया बिक्री पुन: आरंभ करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात की जांच करेगा कि खाता धारक द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रकार का सुधार लाया गया है अथवा नहीं।

"आधार दर निष्पक्षता, पारदर्शिता लाएगी" - डॉ. चक्रवर्ती का कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने यह राय व्यक्त की है कि आधार दर, जिससे कम पर कोई बैंक किसी ग्राहक को उधार नहीं दे सकता, वित्तीय बाज़ार में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का संचार करने की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछेक कम्पनियों ने यह आशंका व्यक्त की है कि आधार दर के परिणामस्वरूप उधार लागतों में वृद्धि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने के बावजूद भी यह वृद्धि होगी। डॉ. चक्रवर्ती ने मत व्यक्त किया है कि इस सुधार का उद्देश्य यही है। "इसके पूर्व "छोटों" द्वारा "बड़ों " को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। बड़ी कम्पनियां 5-6% की दरों पर उधार ले सकती थीं, जबकि लघु एवं मध्यम उद्यम केवल 12-13% पर उधार ले पाते थे। हम इसे रोकना चाहते हैं।" डॉ. चक्रवर्ती इसके आगे भी यह विचार व्यक्त करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक एक ही आवेग में बेचमार्क मूल उधार दरों को लगभग 11-12% से कम करके 7-8% पर लाने में समर्थ हुआ है। इसी क्रम में वह इस बात पर भी बल देते हैं कि

आधार दर प्रणाली (जिसमें आधार दरों की गणना निधियों की लागत के आधार पर की जाती है) अधिक पारदर्शी है तथा इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता आएगी।

यूलिप मानदंडों में परिवर्तनों पर पुनर्विचार नहीं - इर्डा प्रमुख

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरिनारायण द्वारा किए गए दावे के अनुसार यूनिट-सम्बद्ध बीमा योजनाओं (ULIPs) के मानदंडों में हाल के परिवर्तन कायम रहेंगे और उन पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था

जून में निर्यात 30% बढ़कर 17.75 बिलियन डालर हुए

व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात जून में वर्षानुवर्ष 30% बढ़ कर 17.75 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि आयात में 23% की वृद्धि हुई और वह 28.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जिसके फलस्वरूप 10.55 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ। जून में समाप्त तिमाही में निर्यात में 32.25 % का उछाल आया, जिससे वह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 35.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 51 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। आयात में 34% की वृद्धि हुई और वे वर्ष 2009-10 की इसी अवधि के 50.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़ कर 83 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गए। घरेलू मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण इस वर्ष की पहली तिमाही में व्यापार घाटा बढ़ कर अप्रैल-जून 2009-10 के 28.64 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 32.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

जनवरी-मार्च तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़ कर 13.2 बिलियन अमरीकी डालर हुआ

वित्तीय वर्ष 2010 के लिए चालू खाते का घाटा एक वर्ष पहले के 28.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 38.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) में चालू खाते में मालों अथवा सेवाओं की खरीद के समक्ष किए गए लेनदेनों अथवा सेवा से हुई आय को रिकार्ड किया जाता है, जबकि पूंजी खाते का अंतर्वाह निवेश या ऋण सृजित करने वाले ऐसे प्रवाह होते हैं, जो स्वरूप की दृष्टि से अधिक अस्थिर होते हैं। यद्यपि चालू खाते का घाटा पिछले दशक या उसके आसपास वाली अवधि की तुलना में अधिक है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके सम्बन्ध में अनावश्यक चिंता का कोई कारण नहीं है।

विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां

मद	30 जुलाई 2010	30 जुलाई 2010
	के दिन	के दिन
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
कुल आरक्षित निधियां	13,20,311	284,183
(क) विदेशी मुद्रा में आस्तियां	12,01,227	258,551
(ख) सोना	89,564	19,278
(ग) विशेष आहरण अधिकार	23,257	5,006
(घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधियों की स्थिति	6,263	1,348

अंतरराष्ट्रीय समाचार

ईसीबी ने अपनी मुख्य दरें 1% पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.5% पर स्थिर रखीं

यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) ने ब्याज दरों को रिकार्ड कम स्तर पर कायम रखा है, क्योंकि बढ़ती उधार लागतें और सॉवरेन ऋण संकट उक्त क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान को पटरी से उतारने का खतरा बने हुए हैं। नीति-निर्माताओं ने न्यूनतम (बेंचमार्क) दरों को 1% रखा है , इससे अलग हट कर बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) ने अपनी प्रमुख दरें 0.5 % पर स्थिर रखी है।

नयी नियुक्तियां

एचडीएफसी बैंक को नया अध्यक्ष मिला

श्री सी.एम. वासुदेव ने 6 जुलाई, 2010 से एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है।

श्री आर.एम. मल्ला आईडीबीआई बैंक के नये प्रमुख होंगे

श्री आर.एम. मल्ला को आईडीबीआई बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक थे। वे श्री योगेश अग्रवाल का स्थान ले रहे हैं, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो गया।

उत्पाद एवं गंठजोड़

आईएल एवं एफएस ने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की

आईएल एवं एफएस तथा सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), बैंक ऑफ इंडिया (BoI), पंजाब नैशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक - ने "पान-इंडिया पूल्ड सिंडिकेशन फैसिलिटी" नामक एक सुविधा के तहत बड़ी आधारभूत सुविधा और प्रमुख क्षेत्र की परियोजनाओं के समूहन (Syndication) कारबार को सामूहिक रूप से आरंभ करने के लिए एक करार करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा से बड़ी और राष्ट्रीय स्तर वाली आधारभूत सुविधा / मुख्य क्षेत्र की परियोजनाओं के द्रुत गति से वित्तीय समापन में सहायता प्राप्त होगी।

अनिवासी भारतीयों के लिए सेंट्रल बैंक की ऑनलाइन सुविधा

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ न्यूयार्क, मेल्लॉन के सहयोग से अमरीका स्थित अनिवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन विप्रेषण सुविधा की शुरूआत की है। सेन्टफास्ट2इंडिया कही जाने वाली उक्त सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विप्रेषकों द्वारा भारत में स्थित लाभार्थियों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध कराती है। लाभार्थी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर उनके खाते में सीधे जमा के माध्यम से अथवा खाते के अन्य बैंकों के पास रखे जाने की स्थिति में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) के माध्यम से तीन कार्य-दिवसों के भीतर जमा प्राप्त हो जाती है।

वितीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

आर्थिक मूल्य-योजित

किसी कम्पनी के परिचालन लाभ (नकदी आधार पर करों के लिए समायोजित) से पूंजीगत लागत घटाते हुए अवशिष्ट धन के आधार पर परिकलित उसके कार्य-निष्पादन का एक माप।
(इसे "आर्थिक लाभ" भी कहा जाता है।)
आर्थिक मूल्य-योजित की गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है :

= कर-पश्चात् निवल परिचालन लाभ (NOPAT) - (पूंजी * की पूंजीगत लागत) प्रयुक्त पूंजी के प्रतिशत के रूप में

शब्दावली

अंतरण वित्तपोषण

अंतरण वित्तपोषण अल्पावधिक निधीयन स्रोतों को दीर्घावधिक निधीयन स्रोतों में ले जाने का एक साधन होता है। ऋण के पहले पांच वर्षों की व्यवस्था बैंक द्वारा की जाती है और शेष वर्षों के लिए ऋण को मूलभूत संरचना विकास वित्त कम्पनी (IDFC) अथवा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चरल फाइनैन्स कम्पनी लिमिटेड (IIFCL) जैसी सरकार द्वारा स्वाधिकृत संस्थाओं को बेच दिया जाता है, जो बाज़ार से दीर्घकालिक संसाधन जुटा सकती हैं। यह व्यवस्था बैंकों को दीर्घकालिक उधार देने के कारण उद्भूत होने वाले आस्ति देयता असंतुलन से बचने में समर्थ बनाती है।

भुगतान संतुलन

किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान किसी विशिष्ट देश और अन्य सभी देशों के बीच किए गए लेनदेनों की रकमों के डालर अंतर की तुलना करता है। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का अर्थ है देश में आने वाली मुद्रा की तुलना में जाने वाली मुद्रा अधिक और उसके विपरीत स्थिति होना।

महत्वपूर्ण दरें / अनुपात

बैंक दर	8.00 %
पुनर्खरीद (Repo) दर (27/7/2010 से प्रभावी)	5.75 %
प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (reverse repo) दर (27/7/2010 से प्रभावी)	4.50 %
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	6.00 %
सांविधिक चलनिधि अनुपात	25.00 %

अगस्त 2010 माह के लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) /
अनिवासी विदेशी जमाराशियों के लिए बेंचमार्क दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	1.03669	0.7390	1.0660		

विदेशी मुद्रा (बैंक) जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	**अदला-बदली**			
मुद्रा	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**
अमरीकी डालर	1.03669	0.739	1.066	1.432	1.788
ब्रिटिश पौंड	1.47813	1.3930	1.7670	2.1400	2.4450
यूरो	1.39000	1.438	1.678	1.922	2.165
जापानी येन	0.67125	0.438	0.468	0.528	0.588
कनाडाई डालर	1.91792	1.584	1.943	2.247	2.493
आस्ट्रेलियाई डालर	5.60125	4.920	4.980	5.180	5.290

संस्थान समाचार

बैंक क्वेस्ट अब आवधिक प्रकाशन हो गया है। अभ्यर्थी उसे निम्नलिखित आरूप के माध्यम से खरीद सकते हैं:

श्री / श्रीमती / कुमारी : ----------

सदस्यता संख्या :----------

बैंक क्वेस्ट के लिए विद्यमान अभिदान सं. बीक्यू : ----------

डाक का पता : ----------

पिन : ----------टेलीफोन सं. : ---------- ई-मेल : ----------

1 वर्ष (4 अंक) 140.00 रुपये

2 वर्ष (8 अंक) 240.00 रुपये

मैं ---------- रूपये का मांग ड्राफ्ट सं. ---------- दिनांक ---------- संलग्न कर रहा/ रही हूं।

दिनांक :---------- हस्ताक्षर : ----------

टिप्पणी :

1. अभिदान अधिकतम केवल 2 वर्षों की अवधि हेतु ही स्वीकार किया जाएगा।

2. अभिदान मुंबई में देय "इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स" के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार किया जाएगा और फार्म निदेशक प्रशासन, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स , दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, दूसरी मंज़िल, पूर्वी स्कंध, कफ परेड, मुंबई -400005 को भेजे जाने चाहिए।

सीएआईआईबी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

इंस्टिट्यूट इसके पहले यथा घोषित विधि से दिसम्बर, 2010 और उसके बाद से सीएआईआईबी परीक्षा के आशोधित विन्यास की शुरूआत करेगा (अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें)।

सीएआईआईबी (2010) के लिए अध्ययन सामग्री

सीएआईआईबी के लिए अध्ययन सामग्री मैकमिलन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें।

सक्रिय आभासी कक्षाएं

संस्थान ने आगामी जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सक्रिय आभासी कक्षाओं (**सक्रिय** अन्योन्य-क्रिया सम्बन्धी (Interactive) शिक्षण की व्यवस्था की है। अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें।

आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान द्वारा चौथे आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान का आयोजन 28 जुलाई 2010 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 में किया गया। उक्त व्याख्यान डॉ. राकेश मोहन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिवहन विकास समिति, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा "दि फ्यूचर ऑफ फाइनैन्सियल रेग्यूलेशन : सम रिफ्लेक्शन्स" पर दिया गया।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसका 11 वां बैच 23 अगस्त, 2010 से 28 अगस्त, 2010 तक की अवधि हेतु आरंभ होगा।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर

26/07/10 27/07/10 29/07/10 30/07/10 31/07/10

अमरीकी डालर यूरो जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- मध्य माह के आसपास इस आशय की चिंता के आधार पर कि निवेशक उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं में धारिता कम कर देंगे, अब तक किसी एक माह में रुपये में सर्वाधिक गिरावट आई।
- 20वें दिन रुपया कमजोर हो कर 6 सप्ताहों में अपने न्यूनतम स्तर 47.3850 पर पहुंच गया, जो 7 जून 2010 से उसका न्यूनतम स्तर है।
-एनडीएफ खरीद पर डालर की अत्यधिक मांग।
- विदेशी संस्थागत निवेश के 96.9 बिलियन अमरीकी डालर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने के कारण 3रे सप्ताह में रुपये में उछाल।
-रुपये की शक्ति को प्रभावित करते हुए निवल पूंजी अन्तर्वाह 40, 700 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
-माह के दौरान रुपये में मामूली सी मूल्यवृद्धि हुई और वह 46.46 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

भारित औसत मांग दर

6.10
5.90
5.70
5.50
5.30
5.10
4.90
4.70
4.50

02/07/10 03/07/10 05/07/10 06/07/10 07/07/10 10/07/10 12/07/10 13/07/10 19/07/10 21/07/10 23/07/10 24/07/10 26/07/10 28/07/10 30/07/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, जून, 2010

- सामान्य रूप से मांग दरें 5.5% से अधिक पर मंडराती रहीं।

अमरीकी डालर / भारतीय रुपया वायदा

अधिमूल्य / बट्टा (-) 12.00 बजे दोपहर को

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, 2010